MR. CHAIRMAN : Question No. 584.

Memorandum submitted by the Trade Unions of M/s Bridge and Roof

584. SHRI NILOTPAL BASU : Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state :

(a) whether all the trade unions of M/s. Bridge & Roof have submitted a memorandum to the Minister for capital restructuring of the company as well as against disinvestment of the company; and

(b) if so, the response of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES DR. VALLABHBHAI KATHIRIA) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken a decision "in principle" to restructure and convert Bridge & Roof Company (I) Limited into a joint venture company to enable it to grow on a sustainable basis in a competitive environment.

SHRI NILOTPAL BASU : Mr. Chairman, Sir through you, I would like to ask the Hon. Minister whether it is a fact that the company M/s Bridge & Roof prepared and submitted a financial restructuring proposal in 1992 itself and updated and revised its proposal several times. I would like to know whether it is so and why the Government has not taken any decision on such proposals and updated proposals. What is the objective behind the present consideration of these financial reconstruction proposals?

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : सभापति महोदय, जहां तक ब्रिज ऐंड रूफ कम्पनी का सवाल है, 1992 से इसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रपोज़ल आ रहा है लेकिन एक के बाद एक ऐसे प्रश्न वहां उपस्थित हुए हैं कि अभी तक उसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है।

श्री नीलोत्पल बसु : बी.आई.एफ.आर. में नहीं गयी।

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : उसकी पहले कैपीटल रीस्ट्रकचरिंग की बात 1992 में हुई । The purpose behind the financial reconstruction was to enable B & R to improve the financial ratio, equity and debt-service coverage within the FI norms यह 1992 की बात है। उसके बाद 1994 में लोन के कनवर्जन की बात हुई, रीशैडयूलिंग ऑफ इंटरस्ट की बात हुई। फिर 1997 में अपडेटिड कैपिटल रीस्ट्रकचरिंग की बात हुई, यदि ज्वाइंट वैन्चर में जाना है तो उनको डीलिंक करना पड़ेगा। डीलिंक करने की बात हुई तो वहां प्रश्न आया कि इसको डीलिंक करने के लिए प्लानिंग कमीशन में भेजा जाए। डीलिंकिंग की बात भी

नहीं हुई तो 1997 में अपडेटिड कैपीटल की बात हुई कि 1992 का अपडेट करो। उसके आधार पर the proposal for restructuring prepared by the Institute of Financial Management and Research was received from B & R. उन्होंने भी एक प्लान बनाया लेकिन तब भी फिर जनवरी 1998 में The Ministry of Finance has taken a decision regarding disinvestment.

श्री नीलोत्पल बसु : सर, यह अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि आठ साल तक एक कंपनी का प्रपोज़ल लटकता रहा और सरकार खुद यह महसूस नहीं कर पाई कि क्या करना चाहिए ? अगर देखा जाए तो तमाम प्रस्तावों का जो निष्कर्ष है वह यह था कि यह कंपनी अच्छी कंपनी है और इस कंपनी को फाइनेंशियली रीकंस्ट्रक्ट करके यह पी.एस.यू. के तौर पर काम कर सकती है। तो आज जब यह बातचीत दोबारा चल रही है, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस कंपनी को फाइनेंशियली रीकंस्ट्रक्ट करके कंपनी को अपने आप चलाने की इजाज़त देगी या नहीं ? या सरकार ने यह ठान लिया है कि प्राइवेटाइज़ेशन के अलावा इसका कोई चारा नहीं है क्योंकि सरकार का खुद का मन नहीं है ?

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : बात ऐसी नहीं है कि सरकार का मन नहीं है। सरकार ने 1999 तक 8.05 करोड़ का इसको प्लान असिस्टेंस दिया है कंपनी के कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : सर, यही दिक्कत है। हम फाइनेंशियली रीकंस्ट्रक्ट करने के बारे में पूछ रहे हैं और इस सरकार ने क्या असिस्टेंस दिया है, यह बता रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। What is the relevance of that assistance by the Government when the specific question is about the financial reconstruction?

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : देखिए, मैं फाइनेंशियली रीकंस्ट्रक्शन की ही बात कर रहा हूं लेकिन अब तक वहां की जो परिस्थिति है, अभी गवर्नमेंट तो क्लीयर है डिसइनवेस्टमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लीयर है लेकिन एक के बाद एक जो गवर्नमेंट्स आती गईं और जब एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में प्रपोज़ल जाता है तो उनके आधार पर कोई न कोई प्रॉब्लम आती रही अब तक। अभी डीलिंकिंग की बात आई। डीलिंकिंग के बाद एक साल चला गया। एक साल के बाद फिर कंपनी को बताया गया कि अब अपडेट करो तो अपडेट करने की बात आई। जब तक वह पूरा हुआ तब तक जनवरी, 1998 की मैं बात कर रहा हूं, जब अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो इसको ज्वाइंट वेंचर में ले जा सकते हैं, इसीलिए ऐसे विघ्न आते रहे जिनके कारण वह रीस्ट्रक्चर नहीं हुई है। अभी जैसा मैंने कहा कि 8.05 करोड़ दिए हैं और यह कंपनी वैसे भी मार्जिनल प्रॉफिट लेती है, यदि देखा जाए तो केवल 3.2 करोड़ का मार्जिन है उनके प्रॉफिट का। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : अगर यह किया गया तो ऐसा ही होगा।

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ऐसी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको रखना चाहेगी। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यदि स्ट्रेटेजिक ऐसी कोई कंपनी हो तो उनको रखेंगे, बाकी को तो प्राइवेट सेक्टर या डिसइनवेस्टमेंट के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेज दिया है। अब डिसइनवेस्टमेंट डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है कि इसका क्या करना है ?

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और हिंदुस्तान में इसका बहुत नाम है। इसने बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन्स का काम किया है। इसके पास हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं। बोकारो जैसे प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस इन्होंने ही बनाया है। तो आज जब आप जवाब दे रहे हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं इसलिए प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ तो अब तो आपकी सरकार है। क्या इसको फाइनेंशियली रीकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी सरकार, आपका मंत्रालय सोच रहा है ? नंबर दो, डिसइनवेस्टमेंट करने से पहले अगर इसको रीस्ट्रक्चर करके वायेबल बनाने के लिए···· उसमें जो काफी स्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स हाईली हैं, उनको सेव करने के लिए आज के दिन में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना हाई रेट क्वोट कर रहा है, उससे रोकने के लिए सरकार की फाइनेंशियल बचत के लिए ऐसी कंपनी को सुरक्षित रख सकती है ?

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : अभी तक इस कंपनी ने उनका जो लोन एमाउंट है 9.2 करोड़ का, उसका पेमेंट नहीं किया है और उनका जो इंटरेस्ट आया है 31 मार्च, 2000 तक का 52 करोड़ का, वह भी उन्होंने पे नहीं किया है। कंपनी को इनवेस्टमेंट के लिये 112 करोड़ रुपये चाहिये। तो यह तो कंपनी का सवाल है कि उनको कहीं से 112 करोड़ खड़ा करना पड़ेगा। ये तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको स्ट्रेटेजिक नहीं होने के नाते प्राइवेट सेक्टर या ज्वाइंट वेंचर में आगे के लिए दिया जाए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, I have only one question. The question is very clear. The Company has asked for financial restructuring so that it can grow on its own. That is being done in 2000. But that is being done only to facilitate privatisation. What all the employees have asked for is to provide another opportunity for performing better. Can you give them an opportunity? I am asking whether you can give them an opportunity after doing the financial restructuring, which is only book adjustment. Don't give those figures of crores of rupees. It is only book adjustment. After doing the financial restructuring, would you at least permit them to perform for a year or two before

you privatise the Company? मंत्री जी, आप संकोच न करें। यह पहली बार आपकी मेडन रेप्लाई में आया है इसलिए आप एश्योरेंस दे दीजिए कि हां, देखेंगे।

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया : बात यह है कि हम रि-कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन साथ-साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सी पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं जिनको रि-कंस्ट्रेक्ट किया गया है जैसे कि जेसीएफ एंड कम्पनी को 1996 में 54 करोड़ दिया था, लेकिन बाद मे फिर वही पॉजिशन हो गई। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल एक बार रि-कंस्ट्रक्ट करने से उनको फल नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ आइए, हम साथ-साथ बैठकर देख सकते हैं कि हम कैसे रि-कंस्ट्रक्ट करें। लेकिन आपको भी हमें रि-एश्योरेंस देना पड़ेगा कि बाद में यह कम्पनी प्रोफिट में रहेगी।

*585. [The questioner (Shrimati Basanti Sarma) was absent for answer *vide* page 37 *infra*]

औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर

586. **श्री कपिल सिब्बल :** †

डॉ. डी. मस्तान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का कभी आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ङ) ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें इन वर्षों में उत्पादन कम हुआ है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल रख दिया गया है।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछा गया।